



बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./41/एसएलबीसी/दिसम्बर 2014/१५१

06.06.2015

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (30 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

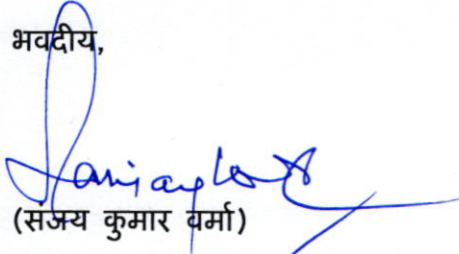
विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2014 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2014 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 25.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,



(संजय कुमार वर्मा)

सहायक महाप्रबन्धक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिनांक 25.02.2015 को सम्पन्न

### बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर' 2014 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 25.02.2015 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री रंजन धवन, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन; श्री सुधीर गर्ग, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (मध्यम, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), उत्तर प्रदेश शासन; श्री सुरेंद्र कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन; श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं श्री मुनीष, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने श्री रंजन धवन, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन; श्री सुधीर गर्ग, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (मध्यम, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), उत्तर प्रदेश शासन; श्री सुरेंद्र कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन; श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं श्री मुनीष, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

➤ प्रदेश में -3000- शाखा - विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक -2868- नयी बैंक शाखाएँ खोल कर एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु सम्मिलित प्रयास किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी जिसका अनुश्रवण राज्य सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर किया जा रहा है। निश्चय ही यह शाखा- विस्तार कार्यक्रम प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार तथा प्रदेश की जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहायक सिद्ध होगा तथा इस प्रकार हमारे प्रदेश में भी population per branch का मानक राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पहुँच जायेगा।

➤ प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम का संचालन राज्य व केन्द्र सरकार के सफल मार्गदर्शन एवं सहयोग से बैंको द्वारा पूरे उत्साह के साथ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी बैंको द्वारा लगभग 1.89 करोड़ खाते खोले गये जिसमें से लगभग 1.69 करोड़ खातों में रुपये कार्ड जारी किये जा चुके हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

हमारे प्रदेश में बैंको द्वारा सभी -27628- एस.एस.ए. व -9404- वार्ड्स में प्रत्येक परिवार का एक खाता खोलने का कार्य करते हुये प्रदेश के सभी -75- जनपदों को संतृप्त घोषित कर दिया गया है जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी व मिशन डायरेक्टर द्वारा -73- जनपदों में जारी किया जा चुका है। शेष -2- जनपदों यथा आजमगढ़ व बुलन्दशहर में इस कार्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार से आवश्यक अनुरोध है।

➤ जहाँ तक वार्षिक ऋण योजना- 2014-15 का प्रश्न है, दिसम्बर' 2014 तक कुल रु 75982.72 करोड़ (66.11%) की उपलब्धि हासिल की गयी है जिसमें और सुधार की आवश्यकता है। मैं सभी बैंकर्स व मौजूद नोडल एजेंसीज से अनुरोध करना चाहूँगा कि मार्च'2015 तक बचे हुए शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास करें ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हम शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति अर्जित कर सकें। हमारे प्रदेश में विगत तिमाही के दौरान सूखा एवं बाढ़ की स्थिति (58 & 18 जनपद क्रमशः) के कारण शायद बैंको की इस उपलब्धि पर विपरीत असर पडा होगा परंतु अब अनुकूल परिस्थितियों के मद्दे नजर बैंको द्वारा प्रयास करते हुए वार्षिक ऋण योजना- 2014-15 के लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

➤ विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बुनकर क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, कामधेनु, मिनी कामधेनु योजना व कुक्कुट पालन, विशेष समन्वित योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में अभी तक की प्रगति इंगित करती है कि इन योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति हेतु बैंको व नोडल एजेंसी के द्वारा और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है।

